सतत विकास के लिए एक साथ आने की जरूरत : गजेंद्र सिंह शेखावत

- इंडिया वाटर वीक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जीएस शेखावत व केंद्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने सत्र को किया संबोधित
- डेनमार्क और भारत के विशेषज्ञों के बीच स्थायी जल प्रबंधन में सहयोग, जल अनुसंधान विकास आदि पर हुई चर्चा

इंडिया वाटर वीक में सत्र को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ● जागरण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : इंडिया वाटर वीक के दूसरे दिन बुधवार को पहले सत्र में भारत और डेनमार्क के विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। स्थायी जल प्रबंधन में सहयोग, जल अनुसंधान विकास आदि पर विचार विमर्श हुआ। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव पंकज कुमार व भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन मौजूद थे। अन्य सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी शामिल हुए।

डेनमार्क के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह भारत सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण और नदियों को साफ करने का कार्य करेंगे। उनके यहां भी भारत जैसी ही स्थिति थी। उनकी नदियां भी गंदी थीं, पर तकनीक का प्रयोग कर ग्रे वाटर प्रबंधन से 90 प्रतिशत पानी को साफ किया गया। 95 प्रतिशत पानी को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया गया। डेनमार्क में एक भी ओवरहेड टैंक नहीं बना है। डेनमार्क की हे नदी का उदाहरण पेश किया गया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ डेनमार्क ने द्विपक्षीय समझौता किया था। इसी के तहत डेनमार्क अपनी तकनीक भारत को देकर उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। तमिलनाडु और खास तौर से हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर प्रायोगिक तौर पर काम शुरू किया है। सेंसर आधारित तकनीकी से डेनमार्क भारत में पेयजल उपलब्धता पर विशेष ध्यान देगा। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने जल जीवन मिशन के कार्यों, भूजल स्तर, ग्रामीण शुद्ध पेयजल उपलब्धता व जल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने, विविध हितग्राहियों को एक साथ लाने, जल संरक्षण में नवाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, पर अभी और काम करने की जरूरत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेयजल की शुद्धता के मानक को सिद्ध करने के लिए 'हर घर में नल और नल से जल मिशन' की सफलता व शुरू किए गए स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भौगोलिक अंतर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सतत विकास के लिए एक साथ आने की जरूरत है।

ओडीएफ पहल का लक्ष्य 2019 तक सफलतापूर्वक पाया गया, जिसे 2030 तक पाने का लक्ष्य तय था। कैलाश चौधरी ने कहा कि आज के समय में पानी का सबसे अधिक उपयोग खेती में हो रहा है। विश्व की कुल भूमि का 328 मिलियन हेक्टेयर हिस्सा भारत का है। कुल पानी का चार प्रतिशत भारत में है, जबकि आबादी 18 प्रतिशत है, जिसमें 50 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के अंदर आता है। आज देश में 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई से खेती की जा रही है। 2016 से लगातार भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पर काम किया गया। इससे ही पानी को बचाया जा सकता है। पाली हाउस और ग्रीन हाउस खेती के लिए सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। आइसीआर ने लगभग 1951 किस्म की फसल तैयार की हैं, जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है।

nwda.gov.in